National Research Journal of Social Sciences
Volume-11, Issue-1, January-June 2026
PP: 545-551

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

भारत में संस्थागत बैंकिंग और कृषि विकास: ग्रामीण परिवर्तन को आगे बढ़ाने में भूमिकाएँ और चुनौतियाँ

वंदना चंद्राकार

शोध छात्रा
वाणिज्य, मैट्स विश्वविद्यालय

कमलजीत कौर

सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य, मैट्स विश्वविद्यालय

संक्षेपिक

भारत में कृषि विकास संस्थागत बैंकिंग और नीति-संचालित वित्तीय प्रणालियों के विकास से काफी प्रभावित हुआ है। यह अध्ययन कृषि विकास, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण परिवर्तन को बढ़ावा देने में बैंकिंग संस्थानों की भूमिका का गुणात्मक विश्लेषण करता है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित संस्थागत ढांचे और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के विकासात्मक हस्तक्षेपों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यात्मक योगदान का विश्लेषण करता है। यह शोधपत्र प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, ब्याज सब्सिडी और वित्तीय समावेशन पहलों जैसे प्रमुख नीतिगत तंत्रों की पड़ताल करता है और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करने और ऋण प्रवाह को बढ़ाने में उनकी प्रभावशीलता का आकलन करता है।

इसके अलावा, यह अध्ययन किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और डिजिटल बैंकिंग जैसे साधनों के माध्यम से किसानों के सशक्तिकरण में बैंकों की भूमिका पर प्रकाश डालता है और व्यवहारिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर उनके प्रभाव पर बल देता है। यह ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करने, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने और संस्थागत क्षमता निर्माण में शीर्ष संस्थानों के योगदान का भी मूल्यांकन करता है। इन उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए, यह शोधपत्र क्षेत्रीय असमानताओं, छोटे और सीमांत किसानों की सीमित पहुंच, संपार्श्विक संबंधी बाधाओं और ऋण वसूली संबंधी मुद्दों सहित लगातार बनी हुई चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। जलवायु परिवर्तनशीलता और वित्तीय स्थिरता जैसे उभरते जोखिमों पर भी चर्चा की गई है। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि यद्यपि बैंकिंग संस्थानों ने भारत में कृषि वित्तपोषण में काफी सुधार किया है, फिर भी दीर्घकालिक स्थिरता और समान ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए अधिक समावेशी, प्रौद्योगिकी संचालित और जोखिम-संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द - कृषि वित्त, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास, बैंकिंग संस्थान

1. भूमिका

कृषि ऐतिहासिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, न केवल अधिकांश आबादी के लिए आजीविका का स्रोत होने के नाते, बल्कि खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में भी। उद्योग और सेवाओं की ओर क्रमिक संरचनात्मक बदलाव के बावजूद, कृषि अभी भी कार्यबल के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करती है और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हालांकि, यह क्षेत्र लंबे समय से खंडित भूमि जोत, मशीनीकरण का निम्न स्तर, अनियमित मानसून पर निर्भरता और आधुनिक संसाधनों तक सीमित पहुंच जैसी संरचनात्मक

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

बाधाओं से ग्रस्त रहा है। इन चुनौतियों ने मजबूत संस्थागत सहायता प्रणालियों की आवश्यकता को जन्म दिया है, जिनमें बैंकिंग संस्थानों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है।

स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक काल में, भारतीय कृषि काफी हद तक साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों जैसे अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर थी। ये स्रोत अक्सर अत्यधिक ब्याज दरें वसूलते थे, जिससे किसान कर्ज और संकट के दुष्चक्र में फंस जाते थे। एक औपचारिक और विनियमित ग्रामीण ऋण प्रणाली के अभाव ने कृषि विकास को बाधित किया और ग्रामीण गरीबी को बढ़ावा दिया। इन सीमाओं को पहचानते हुए, नीति निर्माताओं ने कृषि क्षेत्र को औपचारिक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थागत सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। 1969 में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का सुनियोजित विस्तार हुआ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने नियामक और विकासात्मक कार्यों के माध्यम से कृषि वित्त को आकार देने में मूलभूत भूमिका निभाई है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों को लागू करके, इसने सुनिश्चित किया कि कृषि को कुल बैंक ऋण का अनिवार्य हिस्सा प्राप्त हो। इस नीतिगत हस्तक्षेप से किसानों को संस्थागत वित्त का प्रवाह काफी हद तक बढ़ा, जिससे अनौपचारिक स्रोतों पर उनकी निर्भरता कम हुई। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना ने पुनर्वित्त सहायता प्रदान करके, ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा देकर और संस्थागत विकास को प्रोत्साहित करके ग्रामीण ऋण ढांचे को और मजबूत किया।

समय के साथ, कृषि में बैंकों की भूमिका ऋण प्रदान करने के पारंपरिक कार्य से कहीं आगे विकसित हुई है। आधुनिक बैंकिंग संस्थान अब सिंचाई परियोजनाओं, कृषि मशीनीकरण, भंडारण और प्रसंस्करण अवसंरचना, और डेयरी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों के वित्तपोषण सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कृषि विकास में योगदान दे रहे हैं। वे सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाते हैं, सब्सिडी के कुशल हस्तांतरण को सुनिश्चित करते हैं, और बुनियादी बचत खातों और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्मों जैसी पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। इस बहुआयामी भागीदारी ने बैंकों को कृषि को अधिक उत्पादक और लचीला क्षेत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बना दिया है।

इसके अलावा, बैंकिंग कार्यों में प्रौद्योगिकी के बढ़ते एकीकरण ने कृषि वित्त की सुलभता और दक्षता को बढ़ाया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली, मोबाइल बैंकिंग और डेटा-आधारित ऋण मूल्यांकन उपकरणों ने लेनदेन लागत को कम किया है और सेवा वितरण में सुधार किया है, विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में। इन विकासों ने बेहतर जोखिम प्रबंधन और निगरानी को भी सक्षम बनाया है, जो जलवायु और बाजार की अनिश्चितताओं से स्वाभाविक रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं।

इन प्रगति के बावजूद, कृषि ऋण प्रणाली को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें ऋण वितरण में क्षेत्रीय असमानताएं, छोटे और सीमांत किसानों के लिए सीमित पहुंच और ऋण वसूली से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इसलिए, विभिन्न बैंकिंग संस्थानों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की व्यापक समझ उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आवश्यक है। यह अध्ययन इन भूमिकाओं का गहन विश्लेषण करने का प्रयास करता है, जिसमें यह बताया गया है कि बैंकों ने भारत में कृषि विकास में किस प्रकार योगदान दिया है, साथ ही उन बाधाओं को भी संबोधित किया गया है जो उनके प्रभाव को लगातार बाधित करती हैं।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

2. उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य बैंकिंग संस्थानों की कार्यात्मक भूमिकाओं, संस्थागत तंत्रों और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का गुणात्मक विश्लेषण करना है, ताकि भारत में कृषि विकास पर उनके प्रभाव का पता लगाया जा सके। इसका लक्ष्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में विभिन्न श्रेणियों के बैंकों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन की प्रकृति और सीमा को समझना है, विशेष रूप से ऋण उपलब्धता, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास के संदर्भ में।

एक प्रमुख उद्देश्य कृषि वित्त नीतियों को आकार देने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर निर्देशित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और नियामक भूमिका का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन पुनर्वित्त सहायता, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और अवसंरचना वित्तपोषण के माध्यम से सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के योगदान का मूल्यांकन भी करना चाहता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य यह पता लगाना है कि वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमीनी स्तर पर किसानों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे कार्य करते हैं। इसमें समय पर और पर्याप्त ऋण प्रदान करने, संबद्ध कृषि गतिविधियों का समर्थन करने और सरकारी योजनाओं को सुगम बनाने में उनकी प्रभावशीलता का परीक्षण करना शामिल है। यह अध्ययन लघु एवं सीमांत किसानों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बैंकिंग संस्थानों की भूमिका का आकलन करना भी चाहता है।

इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि बीमा योजनाओं, ऋण पुनर्गठन और विविधीकरण सहायता के माध्यम से बैंक कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने में किस प्रकार योगदान देते हैं। यह अध्ययन कृषि बैंकिंग सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और व्यापक पहुंच में तकनीकी प्रगति के प्रभाव का भी विश्लेषण करता है।

अंततः, इस अध्ययन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने में बैंकिंग संस्थानों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करना है, जिनमें सुलभता, क्षेत्रीय असमानताएं और संस्थागत सीमाएं शामिल हैं। ऐसा करके, यह अध्ययन भारत में कृषि वित्त की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संभावित सुधार और विकास के क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहता है।

3. भारत में कृषि बैंकिंग का संस्थागत ढांचा

भारत में कृषि बैंकिंग का संस्थागत ढांचा बहु-एजेंसी संरचना पर आधारित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। अनौपचारिक ऋण प्रणालियों की सीमाओं और कृषि में संगठित वित्तीय सहायता की बढ़ती आवश्यकता के जवाब में यह ढांचा समय के साथ विकसित हुआ है। सुधार-पूर्व काल में, किसान बड़े पैमाने पर साहूकारों और व्यापारियों पर निर्भर थे, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर शोषणकारी प्रथाएं और दीर्घकालिक ऋणग्रस्तता उत्पन्न होती थी। संस्थागत ऋण का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों को औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क में एकीकृत करने के उद्देश्य से किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ शुरू हुआ, विशेष रूप से प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद।

इस ढांचे के शीर्ष पर भारतीय रिज़र्व बैंक है, जो मौद्रिक नीतियों और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों के माध्यम से कृषि वित्त को विनियमित और निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक ऋण का एक निर्दिष्ट हिस्सा कृषि की ओर निर्देशित हो, जिससे इस क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता को संस्थागत रूप दिया जा सके। इस नियामक भूमिका का पूरक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) है, जो एक विशेष विकास संस्था के रूप में कार्य

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

करता है। NABARD बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है, ग्रामीण अवसंरचना विकास को बढ़ावा देता है और ऋण वितरण तंत्र को मजबूत करता है।

परिचालन संरचना में वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग लेकिन परस्पर संबंधित कार्य करता है। वाणिज्यिक बैंक, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एक व्यापक नेटवर्क रखते हैं और फसल उत्पादन और कृषि निवेश दोनों के लिए बड़े पैमाने पर ऋण प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं और प्राथमिक समितियों, जिला बैंकों और राज्य सहकारी संस्थानों सहित तीन स्तरीय प्रणाली के माध्यम से सुलभ ऋण प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों पर ध्यान केंद्रित करके वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिंग के बीच की खाई को पाटने के लिए बनाए गए हैं।

ये सभी संस्थान मिलकर एक एकीकृत प्रणाली बनाते हैं जो ऋण प्रावधान, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण आर्थिक विकास के माध्यम से कृषि विकास का समर्थन करती है, साथ ही क्षेत्रीय और क्षेत्रीय असमानताओं को भी दूर करती है।

4. कृषि ऋण प्रवाह में नीति और विनियामक भूमिका

भारत में कृषि ऋण को नियंत्रित करने वाली नीति और विनियामक ढांचा इस क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों की दिशा और उपलब्धता दोनों को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों को लागू करके इस प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाई है, जिसके तहत बैंकों को अपने कुल ऋण का एक निश्चित अनुपात कृषि क्षेत्र को आवंटित करना अनिवार्य है। यह नीति संस्थागत वित्त के स्थिर और निर्देशित प्रवाह को सुनिश्चित करती है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों की ओर, जो अन्यथा औपचारिक ऋण बाजारों से वंचित रह जाते हैं।

ऋण लक्षित करने के अलावा, कृषि ऋणों को अधिक किफायती बनाने के लिए ब्याज सब्सिडी योजनाएं लागू की गई हैं। किसानों पर प्रभावी ब्याज भार को कम करके, ये योजनाएं समय पर ऋण लेने और चुकाने को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे ऋण अनुशासन में सुधार होता है और उत्पादकता बढ़ती है। वित्तीय समावेशन पहलों, जिनमें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क वाले खाते, किसान क्रेडिट कार्ड और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं, ने ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को और बढ़ाया है।

इन विनियामक हस्तक्षेपों ने कृषि ऋण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की है और इसके वितरण में सुधार किया है। हालांकि, इन नीतियों की प्रभावशीलता जमीनी स्तर पर उनकी वास्तविक पहुंच पर निर्भर करती है। हालांकि अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता में कमी आई है, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, जो पहुंच, जागरूकता और अंतिम छोर तक वितरण में कमियों को दर्शाती है।

5. शीर्ष और विशिष्ट संस्थानों की विकासात्मक भूमिका

भारत में कृषि वित्त का विकासात्मक आयाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की भूमिका में गहराई से निहित है, जो सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करता है। पारंपरिक बैंकिंग संस्थानों के विपरीत, NABARD एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है जो ऋण सहायता को संस्थागत सुदृढ़ीकरण, अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण के साथ एकीकृत करता है। इसके हस्तक्षेप न केवल वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बल्कि ग्रामीण वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र दक्षता और लचीलेपन में सुधार करने के लिए भी डिज़ाइन किए गए हैं।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

NABARD के प्रमुख कार्यों में से एक सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना है। इस तंत्र के माध्यम से, यह सुनिश्चित करता है कि इन जमीनी स्तर की संस्थाओं के पास किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को ऋण देने के लिए पर्याप्त तरलता हो। यह स्तरित ऋण संरचना अंतिम छोर तक ऋण पहुंचाने को मजबूत करती है और वित्तीय प्रणाली की समावेशिता को बढ़ाती है। इसके अलावा, NABARD सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों, भंडारण सुविधाओं और बाजार अवसंरचना का समर्थन करने वाले समर्पित निधियों के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह के निवेश फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करके और बाजार पहुंच में सुधार करके कृषि उत्पादकता में सीधे योगदान करते हैं।

हस्तक्षेप का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त पहलों को बढ़ावा देना है। अनौपचारिक बचत समूहों को औपचारिक बैंकिंग चैनलों से जोड़कर, नाबार्ड ने हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं और छोटे किसानों के लिए वित्तीय समावेशन को सुगम बनाया है। ये पहलें न केवल ऋण तक पहुंच में सुधार करती हैं, बल्कि सामुदायिक स्तर पर सामूहिक निर्णय लेने और वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा देती हैं।

क्षमता निर्माण और संस्थागत विकास इन प्रयासों की स्थिरता को और बढ़ाते हैं। नाबार्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, अनुसंधान का समर्थन करता है और ग्रामीण वित्त और कृषि में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता है। सामूहिक रूप से, ये हस्तक्षेप एक मजबूत और अनुकूलनीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जो दीर्घकालिक कृषि विकास का समर्थन करता है, भेद्यता को कम करता है और ग्रामीण भारत में टिकाऊ आजीविका प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।

6. वित्तीय समावेशन और किसान सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में बैंकों की भूमिका

भारत में बैंकिंग संस्थानों ने किसानों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे आर्थिक भागीदारी और सामाजिक सशक्तिकरण दोनों को बढ़ावा मिला है। कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन केवल ऋण तक पहुंच से कहीं अधिक व्यापक है; इसमें किसानों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं से जुड़ने में सक्षम बनाना शामिल है जो उनके निर्णय लेने की क्षमता, सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता को बेहतर बनाती हैं। बुनियादी बचत खातों के विस्तार के माध्यम से, बैंकों ने नकदी आधारित अनौपचारिक प्रथाओं से हटकर सुरक्षित और पता लगाने योग्य वित्तीय लेनदेन की ओर बदलाव को प्रोत्साहित किया है। ये खाते बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, आय में अचानक होने वाले झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करते हैं और किसानों के लिए एक वित्तीय पहचान का निर्माण करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कार्यशील पूंजी तक लचीली और समय पर पहुंच प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है। यह उधार लेने की प्रक्रिया को सरल बनाती है और कृषि चक्रों के साथ ऋण उपलब्धता को संरेखित करती है, जिससे किसान इनपुट संबंधी निर्णय अधिक कुशलता से ले पाते हैं। इसी प्रकार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र ने पारदर्शिता को मजबूत किया है और यह सुनिश्चित करके रिसाव को कम किया है कि सब्सिडी और सरकारी सहायता लाभार्थियों तक सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से पहुंचे। इससे औपचारिक संस्थानों में विश्वास बढ़ा है और बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई है। डिजिटल बैंकिंग ने भौगोलिक बाधाओं को दूर करके और सेवा वितरण में सुधार करके वित्तीय समावेशन को और भी गति प्रदान की है। मोबाइल बैंकिंग, आधार से जुड़ी सेवाएं और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वित्तीय लेनदेन को अधिक सुलभ और कुशल बना दिया है। इन नवाचारों ने न केवल लेनदेन लागत को कम किया है, बल्कि औपचारिक वित्तीय प्रणालियों के प्रति जागरूकता और भागीदारी को भी बढ़ाया है। सामूहिक रूप से, ये पहलें वित्तीय साक्षरता को बढ़ाकर, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर और किसानों को निर्वाह आधारित कृषि पद्धतियों से अधिक जानकारीपूर्ण और बाजार उन्मुख कृषि गतिविधियों की ओर अग्रसर करके व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में योगदान देती हैं।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

7. कृषि बैंकिंग में चुनौतियाँ और संरचनात्मक बाधाएँ

संस्थागत विस्तार के बावजूद, भारत में कृषि बैंकिंग को अभी भी गहरी जड़ें जमा चुकी संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी प्रभावशीलता और समावेशिता को सीमित करती हैं। सबसे लगातार चुनौतियों में से एक ऋण वितरण में क्षेत्रीय असमानताओं का अस्तित्व है। बेहतर बुनियादी ढांचे और मजबूत संस्थागत नेटवर्क वाले राज्यों को कृषि ऋण का अनुपातहीन रूप से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर और भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्र वंचित रह जाते हैं। यह असंतुलन समान कृषि विकास के उद्देश्य को कमजोर करता है और क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देता है।

औपचारिक ऋण तक पहुंच विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए सीमित है, जो कृषि आबादी का बहुमत बनाते हैं। उनकी सीमित संपत्ति, औपचारिक दस्तावेज़ीकरण की कमी और कम वित्तीय साक्षरता अक्सर उन्हें संस्थागत ऋण से वंचित कर देती है। संपार्श्विक आधारित ऋण प्रथाएं इस समस्या को और बढ़ा देती हैं, क्योंकि कई किसान ऋण के बदले स्वीकार्य सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। परिणामस्वरूप, कृषि समुदाय का एक वर्ग वित्त के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना जारी रखता है, जिससे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य कमजोर होते हैं।

ऋण वसूली कृषि बैंकिंग की स्थिरता को प्रभावित करने वाली एक और महत्वपूर्ण चिंता है। फसल खराब होना, कीमतों में उतार-चढ़ाव और ऋण माफी जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे कारक ऋण चुकाने के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और ऋण संस्कृति को कमजोर करते हैं। इससे ऋण देने वाली संस्थाओं, विशेष रूप से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ता है, जो संवेदनशील आबादी के करीब काम करते हैं।

जलवायु परिवर्तन जैसी उभरती चुनौतियां कृषि वित्त में एक नई जटिलता जोड़ती हैं। चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति उत्पादन जोखिमों को बढ़ाती है और ऋण मूल्यांकन में अनिश्चितता पैदा करती है। साथ ही, बैंकों पर रियायती और जोखिम-प्रवण ऋण प्रदान करते हुए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का दबाव होता है। ये बाधाएं किसान कल्याण और संस्थागत स्थिरता दोनों को सुनिश्चित करने के लिए नवीन, लचीले और जोखिम-संवेदनशील बैंकिंग दृष्टिकोणों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

8. निष्कर्ष और सुझाव

विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में बैंकिंग संस्थानों ने कृषि वित्त को अनौपचारिक, शोषणकारी प्रणाली से संरचित और नीति-संचालित ढांचे में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे नियामक प्राधिकरणों और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जैसे विकास संस्थानों के समन्वित प्रयासों से कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण का प्रवाह काफी बढ़ा है। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने मिलकर वित्त तक पहुंच में सुधार किया है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को समर्थन दिया है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। हालांकि, क्षेत्रीय असमानताओं का बने रहना, छोटे और सीमांत किसानों तक सीमित पहुंच और ऋण वसूली में चुनौतियां यह दर्शाती हैं कि प्रणाली अपने समावेशी और टिकाऊ उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाई है। जलवायु जोखिमों और बाजार की अनिश्चितताओं का बढ़ता प्रभाव अधिक अनुकूलनीय और लचीले कृषि बैंकिंग ढांचे की आवश्यकता को और भी रेखांकित करता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बैंकों को संपार्श्विक आधारित ऋण से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और फसल आधारित जोखिम प्रोफाइलिंग का उपयोग करते हुए वैकल्पिक ऋण मूल्यांकन मॉडल अपनाने चाहिए। किसानों में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को मजबूत करने से ऋण का प्रभावी उपयोग बढ़

© Copyright @ Authors

ISSN: 2348-473X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.74)
Journal Website: www.nrjss.in

सकता है और पुनर्भुगतान व्यवहार में सुधार हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि पद्धतियों और बीमा से जुड़े ऋण उत्पादों में अधिक निवेश उभरते जोखिमों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय में सुधार से अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं और क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जा सकता है। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए संस्थागत सुधार, साथ ही डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने से वित्तीय समावेशन को और अधिक गहरा किया जा सकता है। ऐसे उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषि बैंकिंग न केवल उत्पादकता को बढ़ावा दे, बल्कि दीर्घकालिक ग्रामीण समृद्धि और स्थिरता में भी योगदान दे।

संदर्भ सूची

1. Reserve Bank of India. (2023). Report on Trend and Progress of Banking in India. Mumbai: RBI Publications.
2. National Bank for Agriculture and Rural Development. (2022). Annual Report. Mumbai: NABARD.
3. Government of India, Ministry of Finance. (2023). Economic Survey of India. New Delhi: Oxford University Press.
4. Food and Agriculture Organization. (2021). The State of Food and Agriculture. Rome: FAO.
5. World Bank. (2022). India: Agriculture and Rural Development Report. Washington, DC: World Bank.

© Copyright @ Authors